संख्या-153/2015/1797/71-1-2015-जी-585/2012

प्रेषक,

राजकुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 02 सितम्बर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/217, दिनॉक 13-07-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-6/2015/2449/71-1-2014-जी-585/2012, दिनॉक 12-01-2015 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 55416.71 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष रू0 575.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश संख्या-49/2015/517/71-1-2015-जी-585/2012, दिनॉक 18-03-2015 द्वारा रू0 1500.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-71/2015/556/71-1-2015-जी-585/2012, दिनॉक 27-03-2015 द्वारा रू0 212.10 लाख कुल रू0 2287.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके उक्त पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में मेडिकल कालेज, जौनपुर के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 47,27,40,000/- (रू0 सैतालिस करोड़ सत्ताइस लाख चालीस हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 25,00,00,000/- (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

4- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप महानिदेशक द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

5- प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- प्रश्नगत प्रायोजना में 20000 व0 मी0 से अधिक क्षेत्रफल में निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, अतः कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नोटिफिकेशन दिनॉक 15 सितम्बर, 2006 के अनुसार पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

7- प्रायोजना के संबंध में एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित नार्म्स एवं वित्त (बजट)-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-07-2014 की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशालता को देखते हुए कि प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यो की प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु महानिदेशक के स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाय तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

9- महानिदेशक का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

10- आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्यो में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

11- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जाये कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-47-राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या:-153/2015/1797(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर।
5- कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।